Foodgrains Requirement for Ration Shops

484. Shrimati Tarkeshwari Sinha: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the minimum Stock of foodgrains required for keeping up the supply line of the ration shops in the country; and

(b) how much of the total requirement is being met by the local supply and how much is met by imports?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) On the basis of the latest rationed population and the current scale of ration, providing for additional issues to heavy manual workers, establishments, etc, the requirement of foodgrains for the statutorily rationed areas works out to 240,000 tonnes per month.

(b) Separate accounts are not maintained in terms of indigenous and imported varieties of foodgrains during issue from Government stocks

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 'काम करने पर भोजन" योजना

485. श्री वे० शि० पाटिल :
श्री ए० बी० पाटिल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सहायता समिति ने सूखाग्रस्तक्षेत्रों में 'काम करने पर भोजन" के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) किन किन राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य के पारिश्रमिक के रूप में भोजन वितरित किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) और (ख) बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुछेक स्वैच्छिक संगठन सहायता कार्य कर रहे हैं । इन संगठनों की गतिविधियो मे कपडे, खाद्यान्न, दूध आदि मुफ्त बांटना और मुफ्त भोजनालय चलाने शामिल हैं । यह ज्ञात नही है कि इन में से कोई संगठन मजदूरी के बदले मे खाद्य देता है ।

राज्य सरकारो ने लोगो को क्रय शक्ति सुलभ करने के लिये सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य संगठित किये हैं और कुछ राज्यो मे कर्मचारियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानो से खाद्यान्न की विशिष्ट मात्राएं खरीदे जिसके लिए वे स्वय निर्धारित दाम देते है । बिहार मे यह प्रबन्ध अभी लागू नही किया गया है और सहायता कार्य पर लगे कर्मचारियो के लिये इसी प्रकार का प्रबन्ध लागू करने के प्रश्न पर वहा विचार हो रहा है ।

Storage of Foodgrains in Punjab

486. Shri P. K. Deo:
Shri G. C. Naik:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri A. Dipa.

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether metal containers of one ton capacity are going to be used in Punjab for storing foodgrains;

(b) its advantages over the conventional method; and

(c) whether such containers will be available at subsidised rates to farmers elsewhere in the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Government of India addressd the State Governments in January last on the subject of providing small storage structures to be used by cultivators with a view to minimise losses in foodgrains in storage with the culti-